भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2844

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के उद्देश्य

2844. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री चिन्तामणि महाराज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ख) वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने लाभार्थियों/परिवारों को शामिल किया गया है; और

(ग) वर्तमान वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितना खाद्यान्न वितरित किया गया हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और ज़रूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोविड संकट को देखते हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का आबंटन नियमित आबंटन के अतिरिक्त था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (चरण I-VII) के तहत 28 महीनों की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था, जिसका कुल नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये था।

गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम की देशव्यापी समरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित करने का निर्णय लिया है। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि को 1 जनवरी, 2024 से 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख): वर्तमान में, 81.35 करोड़ के लक्षित कवरेज की तुलना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 80.56 करोड़ लाभार्थियों (शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8.28 लाख लाभार्थियों सहित) की पहचान की है।

(ग): चालू वित्त वर्ष (दिनांक 31.07.2025 तक) के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 303.42 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया है।

*****